

भारत के BFSI क्षेत्र का पुनरुद्धार

प्रलम्ब के लिये:

[भारतीय रज़िर्व बैंक, पूंजी निर्माण, सतत विकास, वित्तीय समावेशन, बैंक नज़ीकरण, इक्विटी बाज़ार, कॉर्पोरेट बॉण्ड](#)

मेन्स के लिये:

भारत में बैंकिंग, वित्तीय, सेवा और बीमा (BFSI) क्षेत्र की स्थिति, BFSI क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ, भारत के BFSI क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिये उठाए जाने वाले कदम

[स्रोत: द हिंदू](#)

चर्चा में क्यों?

भारत के बैंकिंग, वित्तीय, सेवा और बीमा (BFSI) क्षेत्र को निरंतर संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें फ्रेगमेंट रेगुलेशन, शैलो कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार और अनयिमति शैडो बैंकिंग शामिल हैं, जो सतत विकास के लिये वित्तीय प्रणाली को मज़बूत और स्थिर करने हेतु व्यापक सुधारों की आवश्यकता को उजागर करता है।

भारत के BFSI क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **वर्ष:** BFSI क्षेत्र से तात्पर्य बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा से है, जो सामूहिक रूप से किसी देश के वित्तीय बुनियादी ढाँचे का आधार बनते हैं।
 - इसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC), बीमा फर्म, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और फनिटेक कंपनियाँ जैसी संस्थाएँ शामिल हैं जो व्यक्तियों और व्यवसायों को वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- **भारत के BFSI क्षेत्र की स्थिति:**
 - तीव्र वसति और क्षेत्र की बदलती गतिशीलता: भारत के BFSI क्षेत्र में बाज़ार पूंजीकरण में 50 गुना वृद्धि देखी गई, जो वर्ष 2005 में 1.8 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2025 में 91 ट्रिलियन रुपए हो गया, जिसमें लगभग 22% की CAGR है।
 - जबकि बैंक आधारभूत संरचना बने हुए हैं, कुल बाज़ार पूंजीकरण में उनकी हस्तिसेदारी 85% से घटकर 57% हो गई है, क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) और फनिटेक ने नवाचार और लक्षित वित्तीय समाधानों के माध्यम से अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है।
 - फनिटेक और NBFC का उदय: वर्ष 2015 से, फनिटेक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है, अब इसका मूल्य 12 ट्रिलियन रुपए से अधिक है।
 - इसके साथ ही, NBFC ने भी काफी वसति किया है, जिससे वंचित आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में, ऋण की कमी को पूरा किया जा सका है, जिससे वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है।
 - वित्तीय मज़बूती: नफिटी-50 आय में BFSI क्षेत्र का योगदान (शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध शीर्ष-50 कंपनियों की कुल आय में BFSI उद्योग में कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का हस्तिसे) वित्त वर्ष 2010 में 16% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 33% हो गया, जिससे बेहतर परसिपत्त गुणवत्ता, मज़बूत ऋण मांग और कम प्रावधान का समर्थन प्राप्त हुआ।
 - वित्त वर्ष 24 तक बैंकों की कुल संपत्ति 26 ट्रिलियन रुपए तथा NBFC की 12.4 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गई, जिससे इस क्षेत्र की मज़बूत हुआ।

भारत के BFSI क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **वित्तीय ढाँचा:** भारत का BFSI क्षेत्र खंडित वित्तीय ढाँचे के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें RBI, SEBI और IRDAI जैसे विभिन्न विनियामक विभागों की देखरेख करते हैं।
- इससे क्षेत्राधिकारों में अतव्यापन, वित्तीय अंतराल और असंगत पर्यवेक्षण उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाओं के

- लिये अनुपालन जटिलताएँ और परचालन अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **RBI द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को द्वितीयक बॉण्ड बाज़ार बनाने के निर्देश** को नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग से उच्च लाभ मिलता है, अक्सर अस्पष्ट एल्गोरिथम रणनीतियों के माध्यम से, जिनकी जाँच की जाती है।
 - अवकिसति कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार: भारत का कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार, तरल रहति और अपारदर्शी बना हुआ है, जिससे पूंजी की लागत ऊँची बनी हुई है, जिससे व्यापार व्यवहार्यता और आर्थिक विकास में बाधा आ रही है।
 - भारत का घरेलू कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार, जिसका मूल्य लगभग 64 ट्रिलियन रुपए है, देश के नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद का केवल 18-20% ही दर्शाता है।
 - **स्वामित्व और UBO प्रकटीकरण में अस्पष्टता** भारत को अंतिम लाभार्थी स्वामी (UBO) के प्रभावी प्रकटीकरण की कमी के कारण अपने वित्तीय बाज़ारों में पूंजी प्रवाह और स्वामित्व की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
 - UBO प्रकटीकरण के लिये वर्तमान सीमा (कंपनियों के लिये 10% और साझेदारी के लिये 15%) नवित्तीयों को रपिर्टगि से बचने के लिये अपनी होल्डिंग्स को सीमा से थोड़ा नीचे रखने की अनुमति देती है।
 - नवित्तीय अक्सर UBI नियमों से बचने के लिये प्रकटीकरण सीमा (जैसे, 9.9%) से थोड़ा नीचे अपनी हसिसेदारी रखते हैं, जिससे सेबी की वास्तविक नियंत्रण का पता लगाने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है।
 - कुछ वदेशी पोर्टफोलियो नवित्तीय (FPI) वसितृत स्वामित्व डेटा साझा करने का वसिध करते हैं, जिससे सेबी की नगिरानी कमज़ोर होती है। भारत की वतित्तीय काररवाई कार्य बल (FATE) प्रतबिद्धताओं के बावजूद, खराब कार्यान्वयन प्रवर्तन, पारदर्शिता और नवित्तीय वसिवास को बाधति करता है।
 - **बीमा की कमज़ोर पहुँच:** बढ़ती जागरूकता के बावजूद, भारत में बीमा की पहुँच वैश्विक मानकों के हिसाब से कम है। वर्ष 2023 तक, यह सकल घरेलू उत्पाद का सरिफ 4.2% था, जो सीमति कवरेज और वतित्तीय सुरक्षा जाल के रूप में बीमा के कम उपयोग को दर्शाता है।
 - **गैर-नषिपादति परसिंपततयिँ (NPA):** हाल ही में गरिवट के बावजूद, गैर-नषिपादति परसिंपततयिँ भारतीय बैंकों, वशिष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। खराब ऋणों का उच्च स्तर उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने की उनकी क्षमता को बाधति करता है।
 - दवाला एवं शोधन अक्षमता संहति (IBC) और बैंक पुनर्रपूँजीकरण जैसे उपाय किये गए हैं, फरि भी NPA अनुपात बैंकगि प्रणाली की समग्र दक्षता तथा स्थिरता को प्रभावति कर रहा है।
 - **शैडो बैंकगि जोखमि:** शैडो बैंकगि (जहाँ NBFC, मारजनि ऋणदाता और व्यापक वनियमन के बिना बैंकगि जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं), भारत की वतित्तीय स्थिरता के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा है।
 - खुदरा नवित्तीयों को अक्सर मारजनि ऋण पर उच्च ब्याज दर (20% से अधिक) चुकानी पडती है, क्योंकि ब्रोकर नवित्तीय के स्वयं के धन को वापस उधार देते हैं और पूरी राशि पर ब्याज लेते हैं।
 - इस तरह के अनयिमति ऋण का स्तर नियामकों के लिये अस्पष्ट बना हुआ है, जिससे वतित्तीय स्थिरता के बारे में चतिाएँ बढ़ रही हैं, जो अनयिमति डेरविटवि के कारण उत्पन्न वर्ष 2008 के वैश्विक वतित्तीय संकट के समान है।
 - **साइबर सुरक्षा खतरा:** BFSI क्षेत्र में डिजिटल अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ, साइबर सुरक्षा जोखमि भी बढ़ गए हैं। ऑनलाइन बैंकगि और डिजिटल भुगतान में वृद्धि ने डेटा उल्लंघन, धोखाधड़ी और साइबर हमलों की भेद्यता बढ़ा दी है।
 - साइबर सुरक्षा फर्म कैस्पर्सकाई ने वर्ष 2024 में भारत के वतित्तीय क्षेत्र को लक्षति करते हुए 1.35 लाख से अधिक फशिगि हमलों की सूचना दी थी।

भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित प्रमुख समितियाँ कौन-सी हैं?

क्षेत्र	समिति	मुख्य फोकस
बैंकगि सुधार	नरसहिम समिति	बैंकगि क्षेत्र सुधार, परसिंपतत पुनर्रनिमाण
वित्तीय क्षेत्र में सुधार	रघुराम राजन समिति	समग्र वित्तीय क्षेत्र सुधार
बैंक लाइसेंसिंग	बमिल जालान समिति	नये बैंक लाइसेंस
NBFC वनियमन	ए.सी. शाह समिति	NBFC का वनियमन
सहकारी वित्त	आरएन मरिधा समिति	सहकारी समितियाँ
	मराठे समिति	शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देना
बैंकगि प्रौद्योगिकी	रंगराजन समिति	बैंकों का कम्प्यूटरीकरण
NPA और ऋण संबंधी मुद्दे	खन्ना समिति	गैर-नषिपादति परसिंपततयिँ (NPA)
	एस.एस. कोहली समिति	जानबूझकर चूक करने वाले
वित्तीय समावेशन	नचकिंत मोर समिति	भुगतान बैंक
	एच.आर. खान समिति	बज़िनेस करिस्पोंडेंट (BC) मॉडल
ग्रामीण एवं प्राथमिकता क्षेत्र बैंकगि	एम.एल. दांतवाला समिति	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RBI)
	गाडगलि समिति	अग्रणी बैंकगि योजना
पूंजी बाजार और नविश	सोढानी समिति	वदेशी मुद्रा एवं NRI नविश
	वाई.वी. रेड्डी समिति	लघु बचत सुधार

भारत के BFSI क्षेत्र में सुधार के लिये क्या उपाय लागू किये जा सकते हैं?

- **गहन बॉण्ड बाज़ार का विकास:** भारत का कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 18-20% है, जो दक्षिण कोरिया (80%) और चीन (36%) जैसे देशों से काफी पीछे है।
 - इस बाज़ार को मज़बूत करने से ऋण लेने की लागत कम हो सकती है, दीर्घकालिक पूंजी तक पहुँच में सुधार हो सकता है तथा औद्योगिक विकास और रोज़गार को समर्थन मिल सकता है।
- **KYC और UBO मानदंडों को मज़बूत करना:** वित्तीय नविशों के स्वामित्व और नियंत्रण पर सटीक और सुलभ डेटा सुनिश्चित

- करना। **SEBI** द्वारा **सख्त KYC** और **अंतर्निहित लाभकारी स्वामित्व (UBO)** अनुपालन लागू करने से दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और पूंजी बाजारों में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
- **शेडो बैंकिंग को वनियमित करना:** शेडो बैंकिंग पर्यायों में, विशेष रूप से **NBFC**, **ब्रोकर्स** और **मार्जिन उधारदाताओं** के बीच, व्यापक डेटा संग्रह और पारदर्शिता को अनिवार्य बनाना है।
 - **भारत को यूरोपीय संघ** के समान **नियामक दृष्टिकोण अपनाना** चाहिये तथा सख्त नगिरानी लागू करने से पहले आँकड़ों को आधार के रूप में उपयोग करना चाहिये।
 - **एकीकृत वित्तीय वनियमन:** भारत को **नरीक्षण अंतराल और नियामक वसिगतियों** को दूर करने के लिये **RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA** के बीच **सामंजसपूर्ण वनियमन** की आवश्यकता है।
 - विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में भिन्न **KYC मानदंड अक्षमताएँ** उत्पन्न करते हैं। एक एकीकृत ढाँचा नियामक दक्षता, पारदर्शिता और अनुपालन को बढ़ा सकता है।
 - **NPA सॉल्यूशन में सुधार: एसोसिएट** की गुणवत्ता में सुधार के लिये, **NPA सॉल्यूशन को गति और अधिक कुशल** होना चाहिये।
 - **NCLT और DRT** की क्षमता को मज़बूत करने के साथ-साथ **AIBC को मज़बूत** करने के लिये समर्थन के साथ-साथ इक्विटी में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
 - **बीमा बाज़ार का पुनर्रचना:** निम्न आय वर्ग के लिये **सूक्ष्म आय वर्ग को बढ़ावा** देना तथा मध्यम आय वर्ग को प्रोत्साहन प्रदान करना।
 - दावा प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और समय पर नपिटान सुनिश्चित करना, जिससे विश्वास कायम हो तथा बीमा कवरेज का वसितार हो।
 - **डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना:** जैसे-जैसे डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया बढ़ती है, **साइबर सुरक्षा को मज़बूत** करना महत्वपूर्ण होता है। फाइनेंसियल इनवेस्टमेंट को बेहतर **मार्केटप्लेस का पता लगाना** तथा स्ट्रुडियो के लिये **स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इनवेस्टमेंट** को लागू कर निवेश करना चाहिये।
 - **RBI की Mulehunter.ai** सबसे पहले सुरक्षा और **डिजिटल बैंकिंग** की ओर कदम बढ़ाती है।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के BFSI क्षेत्र में वृद्धि के पीछे के मुख्य कारण क्या हैं? वित्तीय स्थिरता सामने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में इसके आगामी प्रमुख उद्घाटन का परीक्षण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं वनियमन किया जाता है।
2. वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं।
3. उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंकारी वनियमन अधिनियम, 1949 के कार्य-क्षेत्र में लाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर:(b)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है?

- (a) भारतीय बैंक एसोसिएशन
- (b) राष्ट्रीय प्रतभूत निक्षेप लिमिटेड (नेशनल सेक्युरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड)
- (c) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)
- (d) भारतीय रज़र्व बैंक

उत्तर: (c)

???

प्रश्न. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिये आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिये तर्क प्रस्तुत कीजिये। (2016)

